



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, सोमवार, 15 सितम्बर, 2008/24 भाद्रपद, 1930

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 सितम्बर, 2008

**संख्या: डब्ल्यू० एल०एफ०-सी०(10)-6/89-II.**—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मानसिक तौर से अविकसित बच्चों को “प्रेम आश्रम” ऊना में सरकारी खर्चे पर दाखिला दिलवाने हेतु नियम, 1995 जो कि समाज एवं महिला कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या: डब्ल्यू० एल०एफ०-सी (10)-6/89 दिनांक 26-7-1995 द्वारा जारी किए गए थे, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम व प्रवृत्ति.**—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश के मानसिक तौर से अविकसित बच्चों को “प्रेम आश्रम” ऊना में सरकारी खर्चे पर दाखिला दिलवाने हेतु (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 कहलाए जाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र हि०प्र० में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम-6 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश के मानसिक तौर से अविकसित बच्चों को “प्रेम आश्रम” ऊना में सरकारी खर्चे पर दाखिला दिलवाने के नियम 6 में संख्या “25” के स्थान पर संख्या “30” प्रतिस्थापित की जाती है ।

आदेश द्वारा,  
आर० के० जैन,  
प्रधान सचिव ।

## LAW DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11th Sep, 2008*

**No. LLR-E (9)1/88-III (Loose).**—Governor Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Prashant Bhushan, will represent the State of H.P. in the Hon’ble Supreme Court of India as Advocate-on-Record both for Civil and Criminal cases on the terms and conditions as contained in this Department Notification of even No. dated 9/4/2003, with immediate effect.

By order,  
Sd/-  
*LR.Cum-Secretary.*

## आबकारी एवं कराधान विभाग

### अधिसूचना

शिमला-171002, 12-09-2008

**संख्या: ई०एक्स०एन०-ए(१)-१/२००८.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, २००५ (२००५ का अधिनियम संख्यांक १२) की धारा ६३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना सं० ई०एक्स०एन०-ए(५)-४/२००५, तारीख ०२-१२-२००५ द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख ०७-१२-२००५ को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, २००५ में ओर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

1. **संक्षिप्त नाम.**—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियम, २००८ है ।

(२) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम ७७-क, ७७-ख, ७७-ग, ७७-घ, ७७-ङ और ७७-च का अन्तःस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम २००५ के अध्याय ११ “अपील और पुनरीक्षण” में विद्यमान नियम ७७ के पश्चात्

निम्नलिखित नए नियम 77-क, 77-ख, 77-ग, 77-घ, 77-ङ और 77-च अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

**“77(क). अध्यक्ष की अर्हताएं और पद में अन्य निबंधन आदि.—**(1) कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण जिसे हिमाचल प्रदेश कर अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिकरण निर्दिष्ट किया गया है) के नाम से जाना जाएगा, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु तब अर्हित होगा, यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र हो, (कोई अधिवक्ता जिसका किसी उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम दस वर्ष का व्यवसाय हो) या वह हिमाचल प्रदेश सरकार का आयुक्त एवं सचिव हो या रहा हो या वह किसी कर अधिकरण में न्यूनतम पन्द्रह वर्ष के व्यवसाय वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट हो ।

(2) अध्यक्ष से, नियुक्ति पर भारत के संविधान, के प्रति निष्ठा की, पद की गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित प्ररूपों में लेने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :-

### निष्ठा की शपथ का प्रारूप

मैं..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं निष्ठावान रहूंगा और भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा मैं अपने पदीय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा ।

मैं..... हिमाचल प्रदेश कर अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर घोषणा करता हूं कि मैं अपने पदीय कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम योग्यता, जानकारी और विवेकबुद्धि के अनुसार निष्ठापूर्वक पालन करूंगा ।

### गोपनीयता की शपथ का प्रारूप

मैं ..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश कर अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाए अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

3. अधिकरण के अध्यक्ष को, किसी जांच के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया था और आरोपों की बाबत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया था, सिद्ध कदाचार या वित्त-विकृति के कारण अक्षमता के आधार पर के सिवाए, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

4. अधिकरण का अध्यक्ष किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र इसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ।

5. अधिकरण के अध्यक्ष के कार्यालय में होने वाली किसी रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

6. अधिकरण, अपनी अधिकारिता के भीतर, ऐसे स्थान या स्थानों में बैठक करेगा, जैसा यह उचित समझे ।

**77—ख. अधिकरण के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते.—** (1) अधिकरण के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते निम्नलिखित होंगे:—

- (क) यदि वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त सदस्य है, तो उसे सेवानिवृत्ति के समय उसके द्वारा आहत अंतिम वेतन, उसमें से कुल मासिक पेंशन की राशि को घटा कर, मिलेगा, परन्तु उसका वेतन जमा कुल मासिक पेंशन उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय आहत अंतिम वेतन से अधिक नहीं होंगे :

परन्तु अध्यक्ष, आहत अंतिम वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्तों का भी हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, राज्य सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी (ग्रेड) को स्वीकृत किए गए हों :

परन्तु यदि अध्यक्ष अधिवक्ता या चार्टर्ड एकाउंटेंट हो तो उसका वेतन और भत्ते राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव के स्तर के अधिकारियों के वेतन और भत्तों के समान होंगे; और

- (ख) यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवारत सदस्य है, तो वह ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा, जो उसे अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त न होने की दशा में प्राप्त होते थे :

परन्तु यदि अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त होता है, तो उसका वेतन और भत्ते उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के तुरन्त पश्चात् ऐसे होंगे जो इस उप नियम के भाग (क) में उपबंधित हैं ।

**स्पष्टीकरण.—**इस नियम में यथा प्रयुक्त शब्द "कुल मासिक पेंशन" से बिना संराशीकरण के कुल पेंशन अभिप्रेत है ।

- (2) अधिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित का हकदार होगा—

- (क) पदीय कर्तव्यों के संबंध में की गई यात्राओं के लिए ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी (ग्रेड) को अनुज्ञेय है यात्रा भत्ता ।
- (ख) ऐसी चिकित्सा सुविधाएं जो राज्य सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी को अनुज्ञेय हैं; और
- (ग) आकस्मिक छुट्टी और छुट्टी संबलम (वेतन) सहित छुट्टी की ऐसी किस्म जो राज्य सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

**77—ग व्यय आदि.—**अधिकरण के अध्यक्ष और अधिकारियों या कर्मचारियों को या की बाबत देय समस्त वेतनों, भत्तों और पेंशनों सहित अधिकरण का व्यय राज्य की संचित निधि से प्रभारित किया जाएगा ।

**77—घ भविष्य निधि.—**अध्यक्ष, समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 और तदधीन जारी आदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि का अभिदाय करने हेतु चयन करने

का हकदार होगा । यदि वह ऐसा चयन करता है, तो वह अपने भविष्य निधि लेखे से नए भविष्य निधि लेखे में अतिशेष अग्रेषित करने का हकदार होगा ।

**77-ड सेवा की अन्य शर्तें.**—अध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, वही होंगी जो राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव को लागू होती हों ।

**77-च. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और अधिकरण की मुद्रा.**—(1) अधिकरण उसी कार्यालय समय का और वैसी ही छुट्टियों का अनुपालन करेगा जिनका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

(2) अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन इस पर प्राप्ति की तारीख पृष्ठांकित करके रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और तत्पश्चात् इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि करवाई जाएगी ।

(3) अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र अपीलार्थी और प्रत्यर्थी या आवेदक या इस प्रयोजन हेतु नियुक्त उनके अभिकर्ताओं को अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन की सुनवाई हेतु अधिकरण द्वारा नियत की जाने वाली तारीख सूचित करते हुए सूचना दी जाएगी । अपील के ज्ञापन की एक प्रति भी प्रत्यर्थियों को दी जाएगी । अधिकरण संबंधित प्राधिकारी से मामले का अभिलेख मांगेगा ।

(4) सूचना की तामील नियम 84 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।

(5) जब अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन चूक (व्यतिक्रम) में खारिज किया गया हो या उनका एकपक्षीय निपटारा किया गया हो, तो अपीलार्थी या आवेदक अधिकरण को शपथ पत्र द्वारा सम्यक रूप से समर्थित अपील या आवेदन को पुनःग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकता है; और जहां अधिकरण का समाधान करते हुए यह दर्शित किया जाता है कि जब अपील या आवेदन सुनवाई हेतु मांगा गया था तो उसे पर्याप्त कारण से पेश होने से निवारित किया गया था तो अधिकरण अपील या आवेदन पुनः ग्रहण करेगा और ऐसा खर्च जो एक हजार रुपए से अनधिक हो, जैसा अधिकरण निदेश दे, का संदाय करने का आदेश दे सकेगा ।

(6) चूक (व्यतिक्रम) में खारिज या एकपक्षीय निपटारा की गई अपील या आवेदन को पुनः ग्रहण करने के लिए आवेदन ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा :

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि याची को समय पर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित (रोका) किया गया था तो यह तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् आवेदन ग्रहण कर सकेगा ।

(7) सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख, जिसको सुनवाई स्थगित की जाए, को अपीलार्थी या आवेदक या उसके अभिकर्ता की सुनवाई उसकी अपील के समर्थन में सामान्यतः पहले की जाएगी । प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता की, यदि आवश्यक हो, तो तत्पश्चात् सुनवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में प्रत्यर्थी अपील या आवेदन का उत्तर दाखिल (फाइल) करने का हकदार होगा ।

(8) अपीलार्थी या आवेदक अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हों या दस्तावेजी हो, पेश करने का हकदार नहीं होगा, परन्तु यदि—

- (क) प्राधिकारी जिसके आदेश से अपील प्रस्तुत की गई है, ने साक्ष्य, जिसको ग्रहण किया जाना चाहिए था, ग्रहण करने से इंकार किया है; या
- (ख) अपीलार्थी या प्रत्यर्थी अपील में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता हो अधिकरण का समाधान करता है कि ऐसा साक्ष्य, सम्यक तत्परता का प्रयोग करते हुए भी उसकी जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा उस समय या उससे पूर्व जब अपील के अधीन आदेश पारित किया गया था, पेश नहीं किया जा सका था; या
- (ग) अधिकरण ने किन्हीं दस्तावेजों को पेश करने या किसी साक्षी की, अपील में आदेश पारित करने को समर्थ बनाने हेतु, परीक्षा किए जाने की अपेक्षा की हो, तो अधिकरण ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज को पेश किए जाने या साक्षी की परीक्षा किए जाने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा:

परन्तु अन्य पक्षकार, ऐसे मामलों में, साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने या उनका खंडन करने का हकदार होगा ।

(9) यदि अधिकरण की यह राय हो कि, इसके समक्ष किसी मामले के संबंध में किसी साक्षी की परीक्षा की जानी चाहिए, तो यह या तो ऐसे साक्षी की स्वयं परीक्षा कर सकेगा या आबकारी एवं कराधान विभाग के किसी अधिकारी को इसके पक्षकार, जिसे प्रतिपरीक्षा का अधिकार होगा, की उपस्थिति में, साक्षी की परीक्षा करने हेतु कमीशन जारी कर सकेगा ।

(10) अधिकरण, ऐसी शर्तों पर जिन्हें यह उपयुक्त समझे, और किसी भी प्रक्रम (अवस्था) में किसी अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा ।

(11) यदि किसी अपीलार्थी या आवेदक की तब मृत्यु हो जाती है, जब अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन लंबित हो और यह तब तक अग्रसर नहीं हो सकते, जब तक उसके विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर नहीं लाया जाता, तो अधिकरण उसके विधिक प्रतिनिधि को पेश होने और पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए आगामी कार्यवाही स्थगित करेगा । यदि विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थी की मृत्यु से नब्बे दिन के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन का मृत व्यक्ति की बाबत उपशमन हो जाएगा ।

(12) उप नियम 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सुनवाई की समाप्ति और आदेश पारित किए जाने के बीच किसी पक्षकार या प्रत्यर्थी की मृत्यु के कारण कोई उपशमन (समाप्ति) नहीं होगा, परन्तु ऐसे मामले में, मृत्यु के होते हुए भी, आदेश पारित किया जा सकेगा तथा उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि यह मृत्यु होने से पूर्व पारित किया गया था ।

(13) यदि किसी अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मृत अपीलार्थी या प्रत्यर्थी का कोई व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि है या नहीं तो ऐसा प्रश्न अधिकरण द्वारा, यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य लेने के पश्चात्, संक्षेपतः अवधारित किया जाएगा ।

(14) यदि अधिकरण के समक्ष अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के लंबित रहने के दौरान, किसी व्यौहारी, जो एक पक्षकार है, का कारबार किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः या आंशिक रूप में समनुदेशित किया

जाता है या न्यागत होता है, तो अधिकरण, ऐसे समनुदेशिती या ऐसे व्यक्ति जिस पर कारबार न्यागत होता है, के आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति को अपील के पक्षकार के रूप में जोड़ सकेगा ।

(15) यदि कोई व्यौहारी, जो अपील में पक्षकार है, दिवालिया हो जाता है और उसकी सम्पदा समनुदेशिती या रिसीवर में निहित हो जाती है तो, पश्चात्कथित को, अधिकरण की इजाजत से अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन में पक्षकार बनाया जा सकेगा ।

(16) जब कभी किसी मामले में, जहां अपीलार्थी या आवेदक की मृत्यु हो गई थी, समाप्ति या खारिजी का आदेश पारित किया गया है तो उसका (के) विधिक प्रतिनिधि, किसी मामले में जहां अपीलार्थी/आवेदक की मृत्यु हो गई है, अपीलार्थी या आवेदक और किसी मामले में जहां अपीलार्थी या आवेदक दिवालिया हो जाता है और उसकी सम्पदा समनुदेशिती या रिसीवर में निहित हो जाती है, तो ऐसा समनुदेशिती या रिसीवर, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को समाप्ति या खारिजी अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा तथा अधिकरण, इसके समाधान के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर समाप्ति या खारिजी रद्द करेगा और अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन पर अग्रसर होगा ।

(17) अधिकरण अधिनियम के अधीन अपीलों और पुनरीक्षणों की सुनवाई और निपटारा सामान्यतः उनको ग्रहण करने के 6 मास के भीतर और अधिक से अधिक एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर करेगा ।

(18) इन नियमों में अन्य मामलों से संबंधित विहित प्रक्रिया सुसंगत प्रयोजनों के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी ।

(19) अधिकरण की मुद्रा राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त तीन शेरों वाले सामान्य अधिकार चिन्ह सहित "हिमाचल प्रदेश कर अधिकरण" होगी ।

(20) अधिकरण, अपीलों और पुनरीक्षणों के संस्थित किए जाने, उनके निपटान और लंबित होने की विवरणियां, जैसाकि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, आबकारी एवं कराधान विभाग में प्रस्तुत करेगा ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव ।

-----

*[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-A(1)-1/2008, dated 12-09-2008 required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, 12th September, 2008*

**File No. EXN- A (1)-1/2008.**—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value

Added Tax Rules, 2005 which were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 7-12-2005 vide this department Notification No. EXNF (5)-4/2005 dated 2-12-2005, namely:—

**1. Amendments Short Title.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (1st Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

**2. Insertion of rules 77-A, 77-B, 77-C, 77-D, 77-E and 77-F.**—In chapter—XI “APPEAL” AND REVISION” of the Himachal Pradesh Value Added Tax rules, 2005, after existing rule 77, the following new rules 77-A, 77-B, 77-C, 77-D, 77-E and 77-F shall be inserted, namely:—

*“77-A. Qualifications and other terms of office etc. of the Chairperson.*—(1) A person shall be qualified for appointment as the Chairperson of the Appellate Tribunal to be called the ‘Himachal Pradesh Tax Tribunal’ (hereinafter referred to as ‘the Tribunal’) if he has been a Judge of a High Court or he is eligible to be judge of High Court, (an Advocate with a minimum practice of ten years in a High Court or the Supreme Court of India) or he is or has been a commissioner-cum-Secretary to the Government of Himachal Pradesh or he is a Chartered Accountant with a minimum practice of fifteen years in a Tax Tribunal.

(2) The Chairperson, shall on appointment be required to take the oaths of allegiance to the Constitution of India, office and secrecy in the following forms, namely:—

### **FORM OF OATH OF ALLEGIANCE**

I \_\_\_\_\_do\_\_\_\_\_ solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by Law established and that I will loyally carry out the duties of my office.

I \_\_\_\_\_appointed as a Chairperson of the Himachal Pradesh Tax Tribunal do solemnly declare that I will faithfully perform the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment.

### **FORM OF OATH OF SECRECY**

I \_\_\_\_\_do\_\_\_\_\_ solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson of the Himachal Pradesh Tax Tribunal except as may be required for the discharge of my duties as Chairperson.

3. The Chairperson of the Tribunal shall not be removed from his office except on the ground of proved misbehavior or incapacity on account of unsoundness of mind or otherwise after an inquiry made in which such Chairperson had been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of the charges.

4. The Chairperson of the Tribunal may, at any time, in writing under his hand addressed to the State Government resign his office and such resignation shall take effect from the date of its acceptance.



5. A vacancy occurring in the office of the Chairperson of a Tribunal shall be filled in by the State Government in accordance with the provisions of the Act and these rules.

6. The Tribunal shall sit at such place or places within its jurisdiction as it may deem fit.

**77-B. Salary and Allowances of the Chairperson of the Tribunal.**—(1) The salaries and allowances of the Chairperson of the Tribunal, shall be as follows:—

(a) if, he is a retired judge of the High Court or a retired member of the Indian Administrative Service, he shall get the last pay drawn by him at the time of retirement, less the amount of gross monthly pension, but his pay plus gross monthly pension, shall not exceed the last pay drawn by him at the time of retirement.

Provided that the Chairperson shall, in addition to the last pay drawn, be entitled to such allowances as are from time-to-time sanctioned by the State Government to the highest grade of Group 'A' officers of the State Government:

Provided that the salaries and allowances in case of the Chairman being an Advocate or Chartered Accountant, shall be equal to the scale of pay and allowances as are entitled to officers of the level of the Commissioner-cum-Secretary to the State Government; and

(b) if, he is a serving member of the Indian Administrative Service, he shall get such salaries and allowances, as he would have drawn, had he not been appointed the Chairperson of a Tribunal:

Provided that if the person appointed as Chairperson of a Tribunal retires during this tenure as such, his salaries and allowances immediately after the date of retirement, shall be such, as are provided in part (a) of this sub-rule.

**Explanation.**—The words “gross monthly pension” as used in this rule, shall mean the aggregate pension without commutation.

(2) The Chairperson, of the Tribunal, shall be entitled to—

(a) Travelling allowance for journeys performed in connection with the official duties at the rates as are admissible to the highest grade among Group 'A' of the State Government.

(b) such medical facilities as are admissible to the highest grade among Group 'A' Officers of the State government; and

(c) such kind of leave, including casual leave and leave salary as admissible to the Group 'A' officer of the State Government.

**77-C. Expenditure etc.**—The expenditure of the Tribunal including all salaries, allowances and pensions, payable to or in respect of the Chairperson and the officers or officials of the Tribunal shall be charged upon the Consolidated Fund of the State.

**77-D. Provident Fund.**—The Chairperson shall be entitled to elect to subscribe to the General Provident Fund in accordance with the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as amended from time to time and orders issued thereunder. If he so elects, he shall be

entitled to carry forward the balance in his Provident Fund Account to the New Provident Fund Account.

**77-E. Other Conditions of Service.**—The conditions of service of the Chairperson for which no express provisions have been made in these rules, shall be the same as are applicable to the Commissioner-cum- Secretary to the State Government.

**77-F. Procedure to be followed and the seal of the Tribunal.**—(1) The Tribunal shall observe the same office hours and holidays as are observed by the State Government.

(2) An appeal or application for revision shall be registered by endorsing on it the date of its receipt and shall thereafter be caused to be entered in a register to be kept for the purpose.

(3) As soon as may be after the registration of the appeal or application for revision, a notice shall be sent to the appellant and the respondent or applicant or their agents appointed for the purpose intimating the date which the Tribunal may fix for the hearing of the appeal or application for revision. A copy of the memorandum of appeal shall also be furnished to respondents. the Tribunal shall call for the record of the case from the concerned authority.

(4) The service of notice shall be made as per the procedure laid down in Rule 84.

(5) When an appeal or application for revision has been dismissed in default or disposed of *ex parte*, the appellant or the applicant may apply to the Tribunal for re-admission of the appeal or the application duly supported by an affidavit; and where it is shown to the satisfaction of the Tribunal that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal or the application was called for hearing the Tribunal shall re-admit the appeal or the application and may order the payment of such cost not exceeding one thousand rupees as the Tribunal may direct.

(6) An application for re-admission of an appeal or application dismissed in default or disposed of *ex parte* shall be made within thirty days from the date of communication of such order:

Provided that the Tribunal may entertain the application after expiry of the period of thirty days if it is satisfied that the petitioner was prevented by sufficient cause from filing the application in time.

(7) On the date fixed for hearing or on any other date to which the hearing may be adjourned, the appellant or applicant or his agent shall ordinarily be heard first in support of his appeal. The respondent or his agent shall, if necessary, be heard next and in such cases the respondent shall be entitled to file reply to the appeal or the application.

(8) The appellant or the applicant shall not be entitled to produce additional evidence whether oral or documentary before the Tribunal, but if—

(a) the authority from whose order the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or

- (b) the appellant or the respondent in appeal seeking to adduce additional evidence satisfies the Tribunal that such evidence notwithstanding the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at or before the time when the order under appeal was passed; or
- (c) the Tribunal required any documents to be produced or any witness to be examined to enable it to pass order in appeal the Tribunal may allow such evidence or document to be produced or witness to be examined:

Provided that the other party shall, in such cases, be entitled to producer rebutting evidence, if any.

(9) If the Tribunal is of the opinion that any witness should be examined in connection with any case before it, it may either examine such witness itself or issue a commission to any Officer of the Excise and Taxation Department for examining the witness in the presence of the other side who will have the right of cross examination.

(10) The Tribunal may on such terms as it thinks fit, and at any stage, adjourn the hearing of any appeal.

(11) If an appellant or applicant dies while the appeal or application for revision is pending and it cannot be proceeded with unless his legal representative is brought on record, the Tribunal shall adjourn further proceedings to enable his legal representative to appear and apply for being made a party. If the legal representative fails to do so within ninety days from the date on which the appellant dies, the appeal or the application for revision shall abate as regards the deceased.

(12) Notwithstanding anything contained in sub-rule 11 there shall be no abatement by reason of the death of any party or respondent between the conclusion of the hearing and passing of the order, but the order may, in such a case, be passed notwithstanding the death and shall have the same force and effect as if it had been passed before the death took place.

(13) If a question arises in any appeal or application for revision whether a person is or is not the legal representative of a deceased appellant or respondent such question may be determined by the Tribunal in a summary way, if necessary, after taking evidence.

(14) If during the pendency of an appeal or application for revision before the Tribunal, the business of any dealer who is a party is assigned to, or devolves upon some other person either wholly or in part, the Tribunal may, on an application of such assignee or such person on whom the business devolves, add such person as party to the appeal.

(15) If a dealer, who is party to an appeal, becomes insolvent and his estate becomes vested in the assignee or Receiver, the latter, may, by leave of the Tribunal be made a party to the appeal or the application for revision.

(16) Whenever an order of abatement or dismissal has been passed in a case where the appellant or the applicant had died, his legal representative(s), in a case where the appellant/applicant has died, the appellant or the applicant and in a case where the appellant or the applicant becomes insolvent and his estate becomes vested in the assignee or Receiver such assignee or Receiver may, within sixty days from the date of communication of such order apply to the Tribunal for setting aside the abatement or dismissal and the Tribunal shall, on sufficient cause being shown to its satisfaction set aside abatement or dismissal and proceed with the appeal or the application for revision.

(17) the Tribunal shall ordinarily hear and dispose of the appeals and the revisions under the Act ordinarily within six months of their admission and at most within the maximum period of not more than one year.

(18) The procedure prescribed in these rules relating to other matters shall apply mutatis mutandis for the relevant purposes.

(19) The seal of the Tribunal shall be “The Himachal Pradesh Tax Tribunal” with the normal insignia of three lions used by the State Government.

(20) The Tribunal shall submit the returns of institution, disposal and pendency of appeals and revisions as may, from time-to-time, be required by the State Government, in the Department of Excise and Taxation.

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary.

### कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)

#### अधिसूचना

शिमला-171 002 10-09-2008

**संख्या: पर(एपी-बी)ए (3)-7/2003.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र (असाधारण) तारीख 21-9-1973 में यथा प्रकाशित अधिसूचना संख्या: 2-6/71 (नियुक्ति-II) तारीख 20-9-1973 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (छबीसवां संशोधन), विनियम, 2008 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. शैड्यूल का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 से संलग्न शैड्यूल की विद्यमान मद संख्या-12 के पश्चात निम्नलिखित नई मद संख्या-13 अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"13. 50% posts of direct recruitment of Teachers, Engineers and Doctors in Health & Family Welfare, Ayurveda & Animal Husbandry Departments, Himachal Pradesh, (Class-I & II) recruitment to which is made on batch wise basis."

आदेश द्वारा,  
आशा स्वरूप,  
मुख्य सचिव ।

[Authoritative English Text of this department Notification No.Per(AP-B)A(3)-7/2003 dated 10-09-2008, as required under Article 348 (3) of Constitution of India].

## PERSONNEL DEPARTMENT (AP-II)

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 10th September, 2008*

**No.Per(AP-B)A(3)-7/2003.**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Regulations further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973 notified vide notification No.2-6/71 (Apptt.II) dated 20.9.1973 as published in Government of Himachal Pradesh (Extra Ordinary) Rajpatra, dated 21.9.1973, namely:—

**1. Short title and Commencement.**—(i) These regulations may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) (26th Amendment) Regulations, 2008.

(ii) These regulations shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of the Schedule.**—After existing item No.12 of the Schedule attached to the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, the following new item No.13 shall be inserted namely:—

"13. 50% posts of direct recruitment of Teachers, Engineers and Doctors in Health & Family Welfare, Ayurveda & Animal Husbandry Departments, Himachal Pradesh, (Class-I & II) recruitment to which is made on batch wise basis."

By order,  
Asha Swarup,  
Chief Secretary.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 सितम्बर, 2008

**संख्या: टी0सी0पी0-ए(3)-1/95-I.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 30-05-1998 द्वारा अधिसूचित और तारीख 23-3-2004 तथा

12-11-2007 को और संशोधित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. उपाबंध “अ” का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबंध “अ” में :—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों में अंक और शब्द, “24 (चौबीस)” के स्थान पर “19 (उन्नीस)” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव ।

[Authoritative English Text of this department notification no. TCP-A(3)-1/95-I, dated 5-9-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 5th September, 2008*

**No. TCP-A(3)-1/95-I.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Service commission, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Town & Country Planning Department, Planning Officer, Class-I, (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1998 notified *vide* this Department Notification of even number dated 30-5-1998 and further amended on 23-3-2004 and 12-11-2007 namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Planning Officer, Class-I, (Gazetted), Recruitment and Promotion (first Amendment) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure “A”.**—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Planning Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998.

(a) In the existing provision against Column No.2, for the words and figures, “24(Twenty Four)”, the words and figures, “19 (Nineteen)” shall be substituted.

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary.